International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
Volume-11, Issue-1 January-February-2024 P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

भारत के संदर्भ में आतंकवाद की पृष्ठभूमि : एक चुनौती

अभिषेक खोलिया

(शोध छात्र)

रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग

ल. सि. महर रा. स्ना. महाविद्यालय

पिथौरागढ

सारांश 'टेरीरिज्म शब्द Terrorism फ्रांसीसी 'टेरीरिज्म (terrierism)' से आया है, जो लैटिन शब्द 'टेरियो' से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'मैं भयभीत हूं।' यह शब्द शुरू में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान विशेष रूप से 'आतंक के शासन' के संबंध में गढ़ा गया था। आयरिश रिपब्लिकन ब्रदरहुड (1858–1924) को अक्सर समकालीन आतंकवादी रणनीति को नियोजित करने वाला पहला संगठन माना जाता है। वास्तव में, समाज के खिलाफ निर्देशित हिंसा के किसी भी विशेष रूप से जघन्य कृत्य को अक्सर 'आतंकवाद' का लेबल दिया जाता है, चाहे इसमें सरकार विरोधी असंतुष्ट या स्वयं सरकारें, संगठित अपराध समूह या आम अपराधी, उग्रवादी प्रदर्शनकारियों की दंगा करने वाली भीड़, व्यक्तिगत मनोरोगी या अकेला धोखेबाज शामिल है। आतंकवाद (Terrorism)" शब्द काफी व्यापक है और इसकी कोई एक परिभाषा मौजूद नहीं है। विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों ने आतंकवाद की अपनी–अपनी परिभाषाएँ विकसित की हैं।यह एक अवैध और हिंसक व्यवहार है जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा आम जनता में भय पैदा करने और एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जनता और सरकारों को संदेश भेजने के इरादे से किया जाता है। हालांकि आतंकवादी हमला परिस्थितियों के आधार पर केवल कुछ व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है, लक्षित लक्ष्य आमतौर पर पीड़ितों की संख्या से बहुत बड़ा होता है। आतंकवादियों का लक्ष्य आम जनता और सरकार को एक शक्तिशाली संदेश देना है। वे आमतौर पर अपनी शक्ति और क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए हिंसक अपराध करने के बाद दोष का दावा करते हैं और इसलिए जनता को आतंकित करते हैं। आतंकवाद मनोवैज्ञानिक, आपराधिक या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए (अर्ध) गुप्त व्यक्ति, समूह या राज्य के अभिनेताओं द्वारा बार–बार की जाने वाली हिंसक कार्रवाई का एक चिंता–उत्प्रेरण रूप है जिसमें हिंसा के प्रमुख लक्ष्य हिंसा का प्रत्यक्ष लक्ष्य नहीं हैं।

मुख्य शब्द, आतंकवाद. राजनीतिक, संवैधानिक, आर्थिक या सामाजिक संस्थानों आदि

प्रस्तावना, किसी भी आपराधिक कृत्य का इरादा या गणना आम जनता में आतंक की स्थिति को भड़काने के लिए, लोगों के समूह या किसी एक व्यक्ति को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किसी भी परिस्थिति में अनुचित है, चाहे वह राजनीतिक दार्शनिक, वैचारिक, नस्लीय, जातीय धार्मिक या किसी अन्य प्रकृति के विचारों की परवाह किए बिना हो। उन्हें सही ठहराने के लिए बुलाया जा सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग परिभाषा (US Department of State Definition) आतंकवाद को अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा गैर–लड़ाकू लक्ष्यों के खिलाफ उप–राष्ट्रीय समूहों या गुप्त गुर्गों द्वारा की गई पूर्व नियोजित, राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसा के रूप में परिभाषित किया गया है। यूरोपीय संघ की परिभाषा (European Union

Definition) यूरोपीय संघ के अनुसार, आतंकवाद का लक्ष्य "देश के मूल राजनीतिक, संवैधानिक, आर्थिक या सामाजिक संस्थानों को अस्थिर या नष्ट करना" है। एफबीआई परिभाषा (FBI Definition) एफबीआई के अनुसारः "आतंकवाद किसी सरकार को नागरिक आबादी या उसके किसी भी वर्ग को राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए डराने या मजबूर करने के लिए व्यक्तियों या संपत्ति के खिलाफ बल या हिंसा का गैरकानूनी उपयोग है।"

आतंकवाद के महत्वपूर्ण कारण

आतंकवाद के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ का मेरे द्वारा विस्तार के साथ इस शोध पत्र में विस्तार के साथ उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है। राजनीतिक व विद्रोह और गुरिल्ला युद्ध एक गैर–राज्य सेना या समूह द्वारा आयोजित संगठित राजनीतिक हिंसा का एक रूप आतंकवाद सिद्धांत के मूल थे। वे आतंकवाद को इसलिए चुनते हैं क्योंकि वे समाज के मौजूदा ढांचे को नापसंद करते हैं और इसे बदलना चाहते हैं। यह सामान्य रूप से स्वतंत्रता, विकास और मानवाधिकारों के विपरीत हालात है। आतंकवाद का भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेषकर पाकिस्तान की सीमा से लगे क्षेत्रों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। इस बात पर जोर देना कि किसी संगठन के पास आतंकवाद का उपयोग करने का एक रणनीतिक कारण है, यह कहने का एक और तरीका है कि यह एक बेतरतीब या तर्कहीन विकल्प नहीं है, बल्कि एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। उदाहरण के लिए हमास आतंकवादी तकनीकों का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसलिए नहीं कि उसे इजरायल के यहूदियों पर रॉकेट दागने की तर्कहीन इच्छा है। इसके बजाय वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इजराइल और फतह से विशिष्ट रियायतें प्राप्त करने के लिए हिंसा (और संघर्ष विराम) का उपयोग करना चाहते हैं। इसे अक्सर बड़ी सेना या राजनीतिक शक्तियों पर बढ़त हासिल करने के लिए एक कमजोर व्यक्ति की विधि के रूप में माना जाता है। सामाजिक–आर्थिक व आतंकवाद के सामाजिक–आर्थिक सिद्धांतों का अर्थ है कि अभाव के कुछ रूप लोगों को आतंक के कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं या वे आतंकवादी संगठनों द्वारा भर्ती के लिए अधिक खुले हैं। गरीबी, निरक्षरता और राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी इसके कुछ उदाहरण हैं। बहस के दोनों पक्षों में उनके दावों का समर्थन करने के लिए सबूत हैं। विभिन्न निष्कर्षों की तुलना हैरान करने वाली हो सकती है क्योंकि वे व्यक्तियों और समाजों के बीच अंतर नहीं करते हैं और वे इस जटिलता की उपेक्षा करते हैं कि लोग अपनी आर्थिक स्थिति से स्वतंत्र अन्याय या अभाव कैसे महसूस करते हैं। धार्मिक व 1990 के दशक में विशेषज्ञों ने तर्क देना शुरू किया कि धार्मिक उत्साह से प्रेरित एक नए प्रकार का आतंकवाद बढ़ रहा था। उन्होंने उदाहरण के रूप में अल कायदा, ओम् शिनरिक्यो (एक जापानी पंथ) और ईसाई पहचान समूहों का हवाला दिया। भारत में आतंकवादी समूहों में कम्युनिस्ट, इस्लामवादी और अलगाववादी शामिल हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े आतंकवादी समूह अब तक सबसे आम अपराधी हैं और भारत में आतंकवाद से होने वाली मौतों का प्रमुख कारण हैं। कश्मीर में इस्लामी समूहों द्वारा आतंकवादी हमले, पंजाब में सिख अलगाववादी और असम में अलगाववादी आंदोलनों ने भारत को निशाना बनाना जारी रखा है। विभिन्न प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों के बीच अंतर करने के लिए अलग–अलग प्रयास किए गए हैं। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कई अलग–अलग प्रकार के आतंकवादी आंदोलन हैं और कोई भी सिद्धांत उन सभी के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है। न केवल आतंकवादी संगठनों के लक्ष्य, सदस्य, विचार और संसाधन भिन्न होते हैं, बल्कि वे राजनीतिक

वातावरण भी होते हैं जिसमें वे काम करते हैं। अपनी 8वीं रिपोर्ट में, एआरसी–2 निम्नलिखित आतंकवाद प्रतिमान प्रस्तुत करता है।

जातीय–राष्ट्रवादी आतंकवाद जातीय–राष्ट्रवादी और अलगाववादी लक्ष्यों से प्रेरित आतंकवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही प्रमुखता से उभरा और 50 से अधिक वर्षों तक आतंकवादी एजेंडे पर हावी रहा जब तक कि धार्मिक आतंकवाद ने केंद्र मंच नहीं ले लिया। डैनियल बायमैन के अनुसार, जातीय आतंकवाद को "अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए एक उपराष्ट्रीय जातीय समूह द्वारा जानबूझकर हिंसा" के रूप में परिभाषित किया गया है। इस तरह की हिंसा का लक्ष्य अक्सर एक अलग राज्य की स्थापना करना या एक जातीय समूह की स्थिति को दूसरों से ऊपर उठाना होता है। जातीय–राष्ट्रवादी आतंकवादी कृत्यों में श्रीलंका में तमिल राष्ट्रवादी संगठन और उत्तर पूर्व भारत में विद्रोही समूह शामिल हैं।

धार्मिक व विचारधारा उन्मुख आतंकवाद आतंकवादी कृत्य आज दुनिया भर में ज्यादातर धार्मिक अनिवार्यताओं से प्रेरित हैं। हॉफमैन के अनुसार, आतंकवादी जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से एक धार्मिक अनिवार्यता से प्रेरित होते हैं, हिंसा को एक दैवीय दायित्व या एक पवित्र कार्य के रूप में देखते हैं। अन्य आतंकवादी समूहों की तुलना में, यह वैधीकरण और औचित्य के विभिन्न रूपों को अपनाता है, और ये विशिष्ट तत्व धार्मिक आतंकवाद को प्रकृति में अधिक हानिकारक बनाते हैं। आतंक और हिंसा के इस्तेमाल को सही ठहराने के लिए किसी भी विचारधारा का इस्तेमाल किया जा सकता है। विचारधारा से प्रेरित आतंकवाद को आमतौर पर दो श्रेणियों में बांटा गया हैः वामपंथी और दक्षिणपंथी आतंकवाद ज्यादातर तथाकथित वामपंथी मान्यताओं से प्रेरित किसान वर्ग द्वारा हिंसा पूरे इतिहास में कई मौकों पर शासक अभिजात वर्ग के खिलाफ की गई है। लेनिन और माओ त्से–तुंग जैसे कम्युनिस्टों ने अपने लेखन और भाषणों (माओत्से तुंग) में इस धारणा का समर्थन किया। वामपंथी विचारधारा के अनुसार पूंजीवादी समाज में सभी मौजूदा सामाजिक संपर्क और राजनीतिक संरचनाएं प्रकृति में शोषक हैं और हिंसक साधनों के माध्यम से एक क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए पूर्व पश्चिम जर्मनी में रेड आर्मी गुट या बाडर मीनहोफ गिरोह, भारत और नेपाल में माओवादी समूह सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले समूह हैं जो घर के करीब हैं। दक्षिणपंथी संगठन आमतौर पर यथास्थिति बनाए रखने का लक्ष्य रखते हैं या पिछली स्थिति में वापस लौटना चाहते हैं जो उनका मानना है कि संरक्षित किया जाना चाहिए था।[1]

नार्को व साइबर आतंकवाद नार्को आतंकवाद, अपने मूल अर्थ में, नशीली दवाओं के तस्करों द्वारा सरकार या समाज की नीतियों को हिंसा और डराने–धमकाने के साथ–साथ व्यवस्थित धमकी या ऐसी हिंसा के उपयोग के माध्यम से नशीली दवाओं के कानून के प्रवर्तन में बाधा डालने के प्रयासों को संदर्भित करता है। अफगानिस्तान युद्ध में अफीम और हेरोइन की बिक्री के माध्यम से गतिविधियों को निधि देने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों या देशों में वर्तमान या अतीत में मादक द्रव्य आतंकवाद या नार्को–युद्ध अफगानिस्तान है। बॉम्बे बम धमाकों को भारत की डी–कंपनी, मुंबई स्थित एक अपराध गिरोह द्वारा अंजाम दिया गया था। कहा जाता है कि पाकिस्तानी खुफिया जानकारी में उनके लिंक के जरिए वे बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल थे। यह तब होता है जब साइबरस्पेस और आतंकवाद टकराते हैं। यह अवैध हमलों और कंप्यूटर, नेटवर्क पर हमलों की धमकी और उन पर संग्रहीत जानकारी को संदर्भित करता है जो राजनीतिक या सामाजिक लक्ष्यों की खोज में सरकार या उसके नागरिकों को डराने या मजबूर करने के लिए किया जाता है। जैव

आतंकवाद में जैविक एजेंटों की जानबूझकर रिहाई या प्रसार शामिल है। जिस प्रकार जैविक युद्ध में बैक्टीरिया, वायरस, कीड़े, कवक या विषाक्त पदार्थों का उपयोग किया जाता है, उसी तरह ये एजेंट स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो सकते हैं या मानव–संशोधित हो सकते हैं। पिछली बार 1710 में जैविक युद्ध के लिए प्लेग लाशों का इस्तेमाल किया गया था, जब रूसी सेना ने रीगा की शहर की दीवारों पर प्लेग–संक्रमित निकायों को फेंककर स्वीडिश सैनिकों पर हमला किया था।[2]

भारत के सीमा पार आतंकवाद जब किसी एक देश की धरती का इस्तेमाल अपने सीमावर्ती देशों के खिलाफ डर फैलाने या आतंक में लिप्त होने के लिए किया जाता है, तो इसे सीमा पार आतंकवाद के रूप में जाना जाता है। भारत सीमा पार आतंकवाद का शिकार है, जिसका स्रोत पाकिस्तान है। आंतरिक समर्थन : आतंकवादी अक्सर विभिन्न कारणों से स्थानीय लोगों से समर्थन प्राप्त करते हैं, जिसमें वैचारिक या जातीय समानता, भय, मौद्रिक प्रलोभन आदि शामिल हैं। भ्रष्ट अधिकारीः दुर्भाग्य से, किसी देश की संस्था में कई अधिकारी आतंकवादियों की सहायता कर सकते हैं और उन्हें केवल वित्तीय लाभ के लिए आतंकवादी कार्यों के लिए अवैध रूप से देश में प्रवेश करने की अनुमति दे सकते हैं। पोरस सीमाएँः ये दर्शाती हैं कि सीमा अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं है। कठिन भूभाग और अन्य परिस्थितियों के कारण उसके अधिकांश पड़ोसियों के साथ भारत की सीमाओं को भौतिक रूप से सील या तार–तार नहीं किया जा सकता है। दूसरे देश में घुसने के लिए आतंकी संगठन पारगम्य सीमाओं का फायदा उठाते हैं। गैर–राज्य अभिनेताओं से समर्थनः पाकिस्तान के साथ भारत के तनावपूर्ण संबंध अलगाववादी समूहों के समर्थन का समर्थन करते हैं, जिसे पाकिस्तानी नेतृत्व धन, हथियार और प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के साथ–साथ मानवता के शांति और विकास के आवश्यक सिद्धांतों के लिए एक बड़ी चुनौती है। आतंकवादी गतिविधियाँ सरकारों को अस्थिर करती हैं और आर्थिक और सामाजिक प्रगति में बाधा डालती हैं।[3]

भारत में आतंकवाद का प्रभाव कश्मीर में, पूर्वोत्तर और कुछ हद तक पंजाब में भारत को अलगाववादियों के साथ–साथ पूर्व–मध्य और दक्षिण–मध्य भारत में वामपंथी चरमपंथी समूहों से आतंकवाद का सामना करना पड़ता है। 2008 के मुंबई हमले नवंबर 2008 में आतंकवादी हमलों की एक श्रृंखला थी जिसमें एक पाकिस्तानी इस्लामी आतंकवादी संगठन लश्कर–ए–तैयबा के दस सदस्यों ने चार दिनों के दौरान पूरे मुंबई में 12 समन्वित शूटिंग और बमबारी ऑपरेशन किए। भारत दुनिया में आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित देशों में से एक है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के अनुसार, 2018 में भारत सातवां सबसे अधिक प्रभावित देश था। यह कहा गया था कि 2001 और 2018 के बीच भारत में आतंकी हमलों में लगभग 8000 लोग मारे गए थे। देश में आतंकवादी हमलों से जम्मू–कश्मीर राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में भी भारत सातवें स्थान पर था। 2022 के वैश्विक आतंकवाद सूचकांक (GTI) के अनुसार भारत आतंकवाद स्कोर 7.432 के साथ 12वें स्थान पर है। टेरीरिज्म का मुकाबला करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम व गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम 1967 भारत में वर्तमान कानून है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार के आतंकवाद का मुकाबला करना है। 26 नवंबर 2001 को मुंबई पर हुए आतंकवादी हमलों के बाद सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency – NIA) की स्थापना की। 1990 के दशक के उत्तरार्ध से भारत आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (Comprehensive Convention on International Terrorism – CCIT) नामक एक वैश्विक अंतर–सरकारी सम्मेलन पर जोर दे रहा है। भारत फाइनेंशियल

एक्शन टास्क फोर्स (Financial Action Task Force – FATF) का भी सदस्य है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए समर्पित एक वैश्विक संगठन है। भारत अनुसंधान और विश्लेषण विंग (RAW), इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और अन्य सहित खुफिया एजेंसियों का एक नेटवर्क रखता है, जिन्हें देश के अंदर और बाहर आतंकवाद का मुकाबला करने का काम सौंपा जाता है। एक राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (NATGRID) भी है, जो एक एकीकृत खुफिया ढांचा है जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के डेटाबेस को व्यापक खुफिया पैटर्न प्राप्त करने के लिए जोड़ता है जिसे भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) एक अर्धसैनिक समूह है जिस पर आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया गया है।[4]

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग निगरानी एजेंसी है। यह अंतर–सरकारी निकाय, अंतरराष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करता है जिसका उद्देश्य इन अवैध गतिविधियों और समाज को होने वाले नुकसान को रोकना है। नीति बनाने वाली संस्था के रूप में, FATF इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति पैदा करने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। FATF में वर्तमान में 39 सदस्य हैं जिनमें दो क्षेत्रीय संगठन यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद शामिल हैं। भारत FATF का सदस्य है। टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करने के लिए सुरक्षित पनाहगाह माने जाने वाले देशों को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। यह समावेश देश के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि वह काली सूची में प्रवेश कर सकता है। पकिस्तान जून 2018 से FATF की लिस्ट में है। 2012 से 2015 तक भी यह इसी कैटेगरी में था। FATF की ग्रे सूची में होने के परिणामों में IMF विश्व बैंक से आर्थिक प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी और अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार शामिल हो सकते हैं। काली सूची (Blacklist) असहयोगी के रूप में जाने जाने वाले देशों को काली सूची में डाल दिया जाता है। ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं। FATF प्रविष्टियों को जोड़ने या हटाने के लिए नियमित रूप से काली सूची में संशोधन करता है।[5]

निष्कर्ष 1990 में जम्मू और कश्मीर ने आतंकवाद और आतंकवाद विरोधी जवाबी कार्रवाई के लिए ऑपरेशन रक्षक (Operation Rakshak) की शुरुआत की। 2003 में, भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल क्षेत्र से आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन सर्प विनाश (Sarp Vinash) शुरू किया। ऑपरेशन ऑल आउट (Operation All Out) संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम द्वारा शुरू किया गया एक संयुक्त आक्रमण है। जीरो टॉलरेंस नीति भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की वकालत करता है और इससे निपटने के लिए एकल दृष्टिकोण बनाने के लिए काम कर रहा है। भारत ने आतंकवाद और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अन्य देशों के साथ संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Groups – JWGs) स्थापित करने का प्रयास किया है। अन्य देशों ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता (Mutual Legal Assistance – MLAT) पर द्विपक्षीय संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि जांच, साक्ष्य एकत्र करने, गवाहों के स्थानांतरण, स्थान और अपराध की आय के खिलाफ कार्रवाई आदि में तेजी लाई जा सके। जिससे इस देश मे शान्ति हमेशा ही वनी रहे। और इस देश का बुरा चहाने वालों का हम भारतीयों को मिलकर सर्वनास भी करना होगा जिससे भारत शीग्र ही विकसित वन सके ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1 इंडिया एस्सेस्मेंट. 2007 मूल से 16 अगस्त 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 दिसंबर 2009.

2 संग्रहीत प्रति मूल से 9 अगस्त 2009 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 दिसंबर 2009.

3 बिग थ्री' होल्ड की दिल्ली टोक्स । 2008–02–13 ंजीम वेबैक मशीन BBC न्यूज

4 न्यु केरला में भारत, चीन, रूस के विदेशमंत्री सामरिक गठबंधन को बढ़ाने के लिए मिलते हैं 2007–01–24 ंज जीम वेबैक मशीन

5 Indian Police Arrest Islamic Cleric वित ठसेंजे''. Reuters- 05/04/2006. मूल से 28 मई 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 5 अक्टूबर 2009. date में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद)